ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह न्यायधीश के सामने

दीदार सिंह – याचिकाकर्ता

बनाम

चंडीगढ़ और अन्य केंद्र शासित प्रदेश - उत्तरदाताओं

सीडब्ल्यूपी नंबर 2019 का 19833.

26 फरवरी 2020

होम गार्ड अधिनियम, 1947 और नियम, 1963-नियम 18 और 27- दोषसिद्धि के आधार पर होम गार्ड स्वयंसेवक को बर्खास्त कर दिया गया अपीलीय अदालत द्वारा बिना कोई कारण बताए दोषमुक्ति में बदल दिया गया नोटिस या व्यक्तिगत सुनवाई– आदेश टिकाऊ नहीं–प्राधिकरण नहीं कर सकता बाद में समाप्ति को निर्वहन में बदलें।

यह माना गया कि जो दलील अब उत्तरदाताओं द्वारा ली जा रही है किसी गृह का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों के बारे में है 1963 नियमावली के नियम 18 के तहत गार्ड। मुक्ति की उक्त शक्ति नियम 18 के तहत यद्यपि उक्त नियमों के तहत प्रावधान किया गया है लेकिन वह मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह मुद्दा जो खोजा जा रहा है उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी उठाया गया था देविंदर सिंह के मामले में कोर्ट (सुप्रा), जिसका जवाब दिया जा चुका है तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नकारात्मक और मामले की परिस्थितियाँ, जहाँ न्यायालय एक निष्कर्ष पर पहुँचा था जिसके कारण डिस्चार्ज सरलीकरण का आदेश पारित किया गया है वर्तमान मामले में कर्तव्य से अनुपस्थिति, जो इससे स्पष्ट है अनुलग्नक पी-1 (कोली) पर टिप्पणियाँ। याचिकाकर्ता का मामला कवर हो गया है सभी पहलुओं पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुपात से दविंदर सिंह का मामला (सुप्रा)। इसलिए, आक्षेपित आदेश है अस्थिर.

(पैरा 17)

माना, कि एक और पहलू जिस पर प्रकाश डाला गया है
उत्तरदाताओं के वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ता की ओर से देरी हो रही है
बहाली के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करना ही पर्याप्त है कहते हैं कि याचिकाकर्ता ने मुकदमे के समापन का इंतजार किया और यह उसके बाद है अदालत के फैसले, जिसने उसे निर्दोष घोषित किया, कि वह था निर्णय की प्रति के साथ सक्षम प्राधिकारी से संपर्क किया सेवा से बर्खास्तगी का आदेश वापस लिया जाए। इस प्रक्रिया में, वहाँ निस्संदेह, उनकी ओर से कुछ देरी हुई है, लेकिन एक आदर्श के रूप में कर्तव्यनिष्ठ नियोक्ता, यह प्राधिकारी का बाध्य कर्तव्य है किसी कर्मचारी के ऐसे अनुरोध पर विशेष रूप से विचार करें टिप्पणियाँ, जो बरी करते समय ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई हैं उन पर जो आरोप तय किये गये हैं. इतना ही नहीं, कोर्ट ने इसके आधार पर साक्ष्य, बहुत स्पष्ट रूप से देखा गया है कि थोपने की संभावना याचिकाकर्ता पर झूठी वसूली से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसा न्यायालय की टिप्पणियों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है सक्षम प्राधिकारी को कम से कम एक उचित निष्कर्ष पर आना होगा याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार करें, जिसने, माना, नहीं किया है जिनका जवाब दिया गया है और जो आपत्तियां ली गई हैं जो जवाब दाखिल किया गया था, वह यह है कि यह एक अवधि के बाद दाखिल किया गया है उनके बरी होने के पाँच महीने से अधिक समय बाद। ओर से यह दृष्टिकोण वर्तमान के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों में उत्तरदाताओं की मामला अनुचित प्रतीत हुआ। अत: की

आपत्ति उत्तरदाताओं की ओर से देरी होने के संबंध में याचिकाकर्ता पहले उत्तरदाताओं से संपर्क करे और उसके बाद, यह न्यायालय, इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण के अनुसार स्वीकार नहीं किया जाता है याचिकाकर्ता ने एक सामान्य उचित व्यक्ति के रूप में कार्य किया है दिए गए तथ्य और परिस्थितियाँ।

(पैरा 18)

दिव्या शर्मा, अधिवक्ता
याचिकाकर्ता के लिए.

आकांशा साहनी, अधिवक्ता
उत्तरदाताओं के लिए.

ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायधीश.

(1) याचिकाकर्ता ने इसे रद्द करने की प्रार्थना करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है कमांडेंट द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2016 (अनुलग्नक पी-2)। जनरल होम गार्ड-सह-पुलिस महानिरीक्षक, संघ क्षेत्र चंडीगढ़, जिसके तहत याचिकाकर्ता को रिहा कर दिया गया था उनकी सेवाएँ चंडीगढ़ होम गार्ड्स संगठन के रोल में थीं अब आवश्यक नहीं।

(2) यह याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है याचिकाकर्ता को शुरू में होम गार्ड स्वयंसेवक के रूप में नामांकित किया गया था 14.02.2000 और अपनी सेवामुक्ति की तिथि तक इसी रूप में कार्य किया। 23.01.2014. इसके बाद, उन्हें होम गार्ड स्वयंसेवक के रूप में फिर से नामांकित किया गया 12.01.2015 को और आक्षेपित के निधन तक ऐसे ही जारी रहा आदेश दिनांक 21.09.2016 (परिशिष्ट पी-2)। इस दौरान उनका काम और आचरण पर कभी भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई। उनका तर्क है कि ए के खिलाफ शराब बिक्री से संबंधित झूठा आपराधिक मामला दर्ज किया गया था याचिकाकर्ता की धारा 61 के तहत एफआईआर संख्या 115 दिनांक 02.09.2016 है। कथित वसूली के लिए पुलिस स्टेशन कुराली में पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 बिक्री के लिए 'एवरीडे प्रेस्टीज व्हिस्की' नामक शराब की 11 बोतलें केवल चंडीगढ़.

(3) प्राप्त जानकारी का उल्लेख करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम (अनुलग्नक पी-1 कोली) के तहत याचिकाकर्ता, वह तर्क है कि समाप्ति आदेश दिनांक 21.09.2016 (अनुलग्नक पी-2) कमांडेंट जनरल होम गार्ड-सह-इंस्पेक्टर द्वारा पारित किया गया पुलिस महानिदेशक, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, तथ्य पर आधारित है जिसमें उनके खिलाफ उपरोक्त उल्लिखित एफआईआर दर्ज की गई थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. वह डिस्चार्ज की आड़ में इसका विरोध करती है आदेश में याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है वास्तव में, यह सेवा से बर्खास्तगी के समान है और इस प्रकार होगा पंजाब होम गार्ड नियम, 1963 (इसके बाद) के नियम 27 से प्रभावित होंगे '1963 नियम') के रूप में जाना जाता है, जो चंडीगढ़ पर लागू होते हैं होम गार्ड. उनका तर्क है कि उपरोक्त तथ्य के कारण, याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी का आदेश दिया गया था। वह आगे कहती है कि डिस्चार्ज का आदेश दिनांक 21.09.2016 (परिशिष्ट पी-2) था याचिकाकर्ता को कभी नहीं बताया गया और इसलिए, उसके पास कोई नहीं था सरकार के समक्ष अपील दायर करने का अवसर, जैसा कि इसके तहत प्रदान किया गया है नियम। उनका तर्क है कि 1963 की नियमावली के नियम 27 के अनुसार होम गार्ड बल के एक सदस्य की बर्खास्तगी उचित है की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का अवसर

उसके खिलाफ जनादेश दिया गया है, जिसकी आवश्यकता नहीं है जैसा कि याचिकाकर्ता ने डिस्चार्ज के आदेश से पहले किया था, उसका अनुपालन किया गया न तो सुनवाई का मौका दिया गया और न ही कारण बताओ नोटिस दिया गया उसे परोसा गया. उनका तर्क है कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था 02.09.2016 और 09.09.2016 तक न्यायिक हिरासत में रहे। वह, इस प्रकार, दलील दी गई कि याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने का कारण उसकी अनुपस्थिति है कर्तव्य से, जो कदाचार की श्रेणी में आता है जिसके लिए आवश्यकता होती है 1963 नियमावली के नियम 27 को पूरा करना था। उत्तरदाताओं ने नहीं किया है इस तथ्य पर विवाद किया कि उन्हें न तो कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और न ही क्या उसे पारित होने से पहले सुनवाई का अवसर दिया गया था मुक्ति आदेश.

(4) एक और विवाद जो विद्वानों द्वारा उठाया गया है याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि जिस एफआईआर में याचिकाकर्ता के पास है संलिप्त पाया गया है, यह एक झूठा मामला है जिसे थोपा गया है उसे। उनका तर्क है कि मुकदमे के बाद याचिकाकर्ता को सभी दोषों से बरी कर दिया गया है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खरड़ द्वारा निर्णय द्वारा आरोप दिनांक 25.09.2018, जिसमें यह स्पष्ट रूप से निष्कर्ष के रूप में दर्ज किया गया है याचिकाकर्ता पर झूठी वसूली थोपने की संभावना हो सकती है इंकार नहीं किया जा सकता. इस संबंध में उन्होंने दिनांकित निर्णय का हवाला दिया है 25.09.2018 (अनुलग्नक पी-3)। उपरोक्त के आधार पर, के लिए परामर्श याचिकाकर्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता को गलत तरीके से फंसाया गया है आपराधिक मामला, जिसके लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और आरोपमुक्त करने का आक्षेपित आदेश दिनांक 21.09.2016 (अनुबंध पी-2) नहीं दिया जा सकता बनाए रखें और अलग रखे जाने योग्य हैं।

(5) उनका आगे का निवेदन यह है कि याचिकाकर्ता ने एक प्रस्तुत किया है आपराधिक मामले में बरी होने के बाद बहाली के लिए प्रतिनिधित्व 13.03.2019 को (अनुलग्नक पी-4), जिसका जब जवाब नहीं दिया गया, तो ए वकील के माध्यम से दिनांक 24.05.2019 को नोटिस (अनुलग्नक पी-5) दिया गया उत्तरदाताओं पर, जिसे छोड़ने पर फिर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है याचिकाकर्ता के पास इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। वह, इसलिए, दिनांक 21.09.2016 के आक्षेपित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है (अनुलग्नक पी-2) और याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल करना।

(6) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, उसके समर्थन में तर्कों ने माननीय के निर्णय पर भरोसा जताया है दविंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट अन्य 1 जिसमें, के आधार पर समाप्ति के संदर्भ में कदाचार, 1963 नियमावली के नियम 27 का अनुपालन नहीं किया गया है संज्ञान लिया और माना कि स्वयंसेवक बहाली का हकदार है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन के कारण। रिलायंस के पास है सीडब्ल्यूपी संख्या 12594 में इस न्यायालय के फैसले पर भी रखा गया 2014, जिसका शीर्षक 'सकत्तर सिंह बनाम' था। पंजाब राज्य और अन्य, पर निर्णय लिया गया 12.10.2017 और 2012 का सीडब्ल्यूपी नंबर 18043, जिसका शीर्षक 'राकेश कुमार बनाम' है। पंजाब राज्य और अन्य, 28.05.2013 को निर्णय लिया गया (अनुलग्नक पी-6 कोली)।

(7) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के वकील तर्क देते हैं कि होम गार्ड स्वयंसेवक सिविल सेवा नहीं है। यह एक स्वयंसेवक है सेवा, जिसके लिए मानदेय का भुगतान किया जाता है। उन्होंने एक आदेश का हवाला दिया है दिनांक 16.10.2017 को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित, चंडीगढ़ बेंच, OA नंबर 060/00243/2017 में, जिसका शीर्षक 'गौरी शंकर' है बनाम चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य, जहां यह आयोजित किया गया है होम गार्ड स्वयंसेवक, सिविल सेवक नहीं होने के कारण नहीं वैधानिक अधिकार, की धारा 19 के तहत ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम,

1985। इसे आगे प्रस्तुत किया गया है उत्तरदाताओं के लिए वकील कि 1963 के नियमों के नियम 18 के अनुसार, शक्ति नियुक्ति प्राधिकारी को किसी सदस्य को सेवामुक्त करने की अनुमति तब दी जाती है जब वह सेवा की अब आवश्यकता नहीं है. आगे कहा गया है कि 1963 के अनुसार नियम, होम गार्ड स्वयंसेवकों के पुनर्नियोजन का कोई नियम नहीं है और इसलिए, एक मामले के रूप में बहाली की मांग/माँग नहीं की जा सकती अधिकार का. यह एक स्वयंसेवी संगठन और स्वयंसेवक है इसका हिस्सा बनने के लिए स्वयं को प्रस्तुत/प्रस्तावित करें। उनका आगे का तर्क यह है याचिकाकर्ता दो शब्दों 'डिस्चार्ज' और 'बर्खास्तगी' को मिला रहा है। बर्खास्तगी 1963 के नियमों के नियम 18 के अंतर्गत आती है, जबकि बर्खास्तगी धारा 27 के तहत प्रदान किया गया है। तत्काल मामले में, सक्षम प्राधिकरण ने दिनांक 21.09.2016 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को आरोपमुक्त कर दिया है (अनुलग्नक पी-2) और उसे सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया है, इसलिए, नियम 1963 के 27 नियम लागू नहीं होंगे।

(8) हालाँकि, यह उसके द्वारा स्वीकार किया गया है कि छुट्टी का आदेश है एक एफआईआर का नतीजा, जो याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई थी, ऊपर उल्लिखित, और उक्त मामले में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी। इस में संबंध में, उत्तरदाताओं के वकील द्वारा यह बताया गया है कि उक्त कार्रवाई को बनाए रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी थी और संगठन में जनता का विश्वास बहाल करें। उसके आगे तर्क यह है कि याचिकाकर्ता को इस तथ्य के बारे में अच्छी तरह से पता था कि उसके पास यह है विचाराधीन रहने के दौरान दिनांक 21.09.2016 को ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया मुक़दमे और जमानत के बाद उनके द्वारा अपनी सफ़ाई के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया न ही उनके द्वारा नियम 14.5 के तहत कोई अपील दायर की गई, जो कि झूठ है सरकार को, नोटिस देने की तारीख से 30 दिनों के भीतर उस पर संबंधित आदेश की तामील की गई। वह आगे कहती है कि याचिकाकर्ता को न्यायालय द्वारा दिनांक 25.09.2018 के निर्णय द्वारा बरी किये जाने पर (अनुलग्नक पी-3) में जो एफआईआर उन्होंने दोबारा दर्ज कराई थी दिनांक 13.03.2019 को ही बहाली हेतु अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जो लगभग साढ़े पांच महीने की अवधि के बाद है। इससे यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता को अपनी रिहाई के बारे में पता होने के कारण उसने इसे चुनौती नहीं दी थी इस विलंबित चरण में, राहत के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। दावा याचिकाकर्ता की याचिका देरी के आधार पर ही खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार, रिट याचिका को खारिज करने के लिए प्रार्थना की गई है।

(9) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने भरोसा जताया है 2014 के सीडब्ल्यूपी नंबर 2680 में इस न्यायालय के फैसले पर, जिसका शीर्षक है 'जतिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य' पर फैसला सुनाया गया 08.01.2008, जिसमें यह माना गया है कि एक व्यक्ति संविदा पर काम कर रहा है आधार को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और एफआईआर में शामिल होने पर उनका उनकी प्रकृति को देखते हुए सेवाएँ उचित रूप से समाप्त कर दी गईं रोज़गार। उसके बाद बरी होने से स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है याचिकाकर्ता को पद पर रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। रिलायंस के पास भी है इस न्यायालय द्वारा CWP No.19229 में पारित निर्णय पर रखा गया है 2018 का, शीर्षक 'जोगिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और' अन्य', 17 अन्य रिट याचिकाओं के साथ 06.06.2019 को निर्णय लिया गया, जहां यह देखा गया है कि होम गार्ड स्वयंसेवकों को स्थायी, अस्थायी, तदर्थ या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नहीं माना जा सकता है, लेकिन केवल एक स्वयंसेवक. के पैरा 14.4 का भी संदर्भ दिया गया है द्वारा जारी किए गए होम गार्ड संबंधी अनुदेशों का सार-संग्रह भारत सरकार, जिसके अनुसार सक्षम प्राधिकारी कर सकता है किसी स्वयंसेवक को किसी भी समय कर्तव्य से मुक्त करना, यदि उसकी राय में, ऐसे स्वयंसेवक की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है।

(10) मैंने पार्टियों के विद्वान वकील को सुना है सहायता याचिकाओं के साथ-साथ निर्णयों से भी गुज़री है जो भरोसा रखा गया है.

(11) पहली दलील जिसका उत्तर दिया जाना आवश्यक है, वह है याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका की पोषणीयता होम गार्ड स्वयंसेवक, जिस पर टिप्पणी की गई है कि वह नहीं है सिविल सेवा लेकिन इसकी स्थिति के रूप में स्वयंसेवी सेवा स्थायी नहीं है या अस्थायी या तदर्थ या दैनिक वेतन जैसा कि इस मामले में इस न्यायालय ने देखा जोगिंदर सिंह के मामले (सुप्रा) पर भरोसा किया गया है उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील।

(12) यह सच है कि इस न्यायालय की टिप्पणियों के अनुसार
उपर्युक्त निर्णय, नियुक्ति की प्रकृति और स्थिति होम गार्ड वालंटियर को स्थाई, अस्थाई नहीं माना जा सकेगा। तदर्थ या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी लेकिन उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ हैं पंजाब होम गार्ड के रूप में क़ानून के प्रावधानों द्वारा शासित संगठन का गठन पंजाब होम गार्ड अधिनियम, 1947 के तहत किया गया है (इसके बाद '1947 अधिनियम' के रूप में संदर्भित)। 1963 की नियमावली रही है 1947 की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाया गया कार्यवाही करना। सभी नियुक्तियाँ होम गार्ड स्वयंसेवकों के लिए की जाती हैं यह 1947 अधिनियम और 1963 नियम, जो स्वीकार्य रूप से लागू होते हैं चंडीगढ़ होम गाड्र्स। केवल इसलिए कि, वे स्वयंसेवक हैं इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास कोई भी अधिकार या अधिकार नहीं है 1947 अधिनियम एवं 1963 नियमावली के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही कर सकती है उक्त अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों की मनमाने ढंग से अनदेखी की जा रही है। मामले में ए कर्मचारी उल्लंघन का आरोप लगाते हुए शिकायत लेकर न्यायालय पहुंचता है उपरोक्त अधिनियम और नियमों के प्रावधान, यह न्यायालय अभ्यास में है भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इसकी शक्ति प्रदत्त है, अधिकार क्षेत्र और उसके प्रयोग के अधिकार से वंचित नहीं होगा न्यायिक समीक्षा की शक्ति. न्यायालय, दिए गए तथ्यों में और हो सकता है मामले की परिस्थितियाँ, अपनी शक्ति का प्रयोग करने से इंकार या परहेज करती हैं हालाँकि, इस मामले में गहराई से जाने के लिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि स्वयंसेवक होम गार्ड संगठन में सेवा करने वालों को उनका कोई अधिकार नहीं है सेवाएँ चिंतित हैं और अधिकारियों की दया पर निर्भर हैं, जो कर सकते हैं असहायों को छोड़कर अपनी सनक और पसंद के अनुसार अपने विवेक का प्रयोग करें बिना किसी उपाय के स्वयंसेवक।

(13) उपरोक्त के आलोक में, यह न्यायालय इसका अभ्यास कर रहा है इसलिए, न्यायसंगत रिट क्षेत्राधिकार पर विचार करने के लिए आगे बढ़ना होगा याचिकाकर्ता की शिकायत उसके तर्कों के आलोक में है कि नियम 27 एक आदेश की आड़ में उत्तरदाताओं द्वारा 1963 नियमों का उल्लंघन किया गया है डिस्चार्ज का शब्द दिया गया है इसलिए यह एक सज़ा है, जो किया गया है याचिकाकर्ता पर कथित कदाचार यानी अनुपस्थिति के लिए लगाया गया उसकी गिरफ्तारी और उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने के कारण ड्यूटी उसे।

(14) परिशिष्ट पी-1 (कोली) के अवलोकन से जो हैं उत्तरदाताओं की टिप्पणियाँ, जैसा कि याचिकाकर्ता को अधिकार के तहत प्रदान किया गया है सूचना अधिनियम के अनुसार, यह स्पष्ट है कि यद्यपि ये पहलू याचिकाकर्ता की ड्यूटी से अनुपस्थिति और उसकी गिरफ्तारी के संबंध में बर्खास्तगी के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को आधार बनाया गया याचिकाकर्ता की सेवाओं की पूर्ति की आवश्यकता से बचने के लिए 1963 की नियमावली का नियम 27 जो यथावत् आकर्षित होगा यह याचिकाकर्ता की ओर से कदाचार की श्रेणी में आता है, प्रतिवादी नंबर 4 ने बर्खास्तगी का आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़े, जो टिकाऊ नहीं है देविंदर मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर

प्रकाश सिंह का मामला (सुप्रा), जहां पैरा 25 से 33 में इसे माना गया है इस प्रकार है:-

> "(25) उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ताओं को 1963 के नियमों के नियम 18 के तहत आरोपमुक्त कर दिया गया होम पर निर्देशों के सार-संग्रह के पैरा 14.4 को पढ़ें रक्षक। 1963 का नियम 18 पढ़ता है: "सदस्यों की छुट्टी :- किसी भी सदस्य को छुट्टी दी जा सकती है किसी भी समय उस प्राधिकारी द्वारा जिसने उसे नियुक्त किया था उनकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है।"
>
> (26)इसके द्वारा अभिव्यक्ति 'डिस्चार्ज' की व्याख्या की गई केरल राज्य बनाम मदर अनास्तासिया के मामले में न्यायालय, सुपीरियर जनरल और अन्य (1997) 10 एससीसी 79, जिसमें, यह कहा गया है, "डिस्चार्ज का अर्थ किसी अन्य कारण से होगा पद या प्रक्रिया के उन्मूलन के कारण एजुस्डेम जेनेरिस देय छुट्टी को छोड़कर अध्ययन या ऐसी ही समान परिस्थितियाँ कदाचार करना।"
>
> (27) उपरोक्त नियम पर विचार नहीं किया गया है जांच करने या नोटिस देने की आवश्यकता संबंधित व्यक्ति और, इसलिए, उत्तरदाताओं का कहना है कि समाप्ति आदेश इसलिए दायरे में था और होम गार्ड अधिनियम, 1947 और 1963 नियमों की योजना उसके तहत बनाया गया.
>
> (28) अपीलकर्ताओं की सेवाएँ समाप्त करने का आदेश विशेष रूप से अमृतसर रेलवे में अनुशासनहीनता का हवाला देता है समाप्ति के कारण के रूप में स्टेशन. इसलिए, यह एक नहीं है ऐसा मामला जहां नियुक्ति प्राधिकारी निर्वहन कर रहा है अपीलकर्ताओं की सेवाएं इस आधार पर कि उनकी सेवाएं अब आवश्यकता नहीं है लेकिन यह एक ऐसा मामला है जहां उनकी सेवाएं के आधार पर दूर करने की मांग की गई है अनुशासनहीनता, जो के अर्थ में आयेगी अभिव्यक्ति 'कदाचार'. ऐसी स्थिति में उत्तरदाता अपीलकर्ताओं की सेवाएं समाप्त नहीं कर सकते के नियम 27 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना नियम, उक्त नियम, विशेष रूप से अनुशासन से संबंधित हैं। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-
> "बर्खास्त :- (1) कोई भी अधिकारी कदाचार के लिए या के लिए बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहने पर सेवा से बर्खास्त किया जायेगा।
>
> बशर्ते कि बर्खास्तगी का आदेश पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि बर्खास्तगी का कारण लिखित रूप में दर्ज न किया गया हो संबंधित सदस्य को उचित अवसर दिया गया है की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का उसके खिलाफ।"
>
> (29) नियम में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट है असंदिग्ध. नियम में यह प्रावधान है कि कोई भी अधिकारी हो कदाचार के लिए या तो सेवा से बर्खास्त कर दिया गया अनाधिकृत अनुपस्थिति. नियमों के साथ संलग्न परन्तुक कहता है दोषी अधिकारी को सुनवाई का अवसर देना या अधिनियम और नियमों के तहत नियुक्त सदस्य। यह है एक स्वीकृत स्थिति कि सुनवाई का ऐसा कोई अवसर नहीं है या वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं को यथास्थिति नोटिस दिया गया था नियम के तहत आवश्यक है

27.मामले के इस दृष्टिकोण में, उत्तरदाता नहीं हो सकते यह तर्क देने की अनुमति दी गई कि अपीलकर्ता 'स्वयंसेवक' हैं,इसका अनुपालन किए बिना उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं वैधानिक नियमों में निर्धारित प्रक्रिया, जो व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने की बात करता है प्रस्तावित कार्रवाई से कौन प्रभावित होंगे।

(30) हमें, अधिनियम और को पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है इसके तहत बनाए गए नियम, कि अभिव्यक्ति 'स्वयंसेवक' ऐसा प्रतीत होता है कि यह मिथ्या नाम है। हमारा इस पर ध्यान केन्द्रित करने का इरादा नहीं है मुद्दा, चूँकि हमें बताया गया है कि रिट याचिकाएँ समान पद पर नियुक्त व्यक्तियों का नियमितीकरण पहले से लंबित है उच्च न्यायालय. द्वारा प्रस्तुत तथ्य एवं परिस्थितियाँ अपीलकर्ता और उनके द्वारा बिताए गए वर्षों की संख्या 'स्वयंसेवक' और चूंकि उनके पास अपने लिए कोई अन्य रास्ता नहीं है उनके आयु कारक के कारण वैकल्पिक रोजगार, हम हैं की समाप्ति के कारणों पर गौर करने के लिए प्रेरित किया अपीलकर्ताओं की सेवाएं. पत्र उनका निर्वहन सेवाएँ स्पष्ट रूप से बताती हैं कि छुट्टी का कारण है अपीलकर्ताओं के समक्ष अमृतसर रेलवे स्टेशन पर अनुशासनहीनता चुनाव ड्यूटी पर महाराष्ट्र के लिए ट्रेन पकड़ने वाले थे। इसलिए, हमारी राय में, यह डिस्चार्ज का मामला नहीं है सरल बनानेवाला। 1963 नियमावली के नियम 18 के तहत कोई भी सदस्य नियमों के तहत नियुक्त किये गये व्यक्ति को किसी भी समय सेवामुक्त किया जा सकता है वह प्राधिकारी जिसने उसे तब नियुक्त किया था जब उसकी सेवाएँ हैं अब आवश्यक नहीं। यदि यह डिस्चार्ज सिम्प्लिसिटर का उदाहरण है, यह आवश्यक रूप से उन उदाहरणों से संबंधित होगा जहां पोस्ट है समाप्त कर दिया गया है या जहां कर्मचारियों की अधिकता है या अन्य समान परिस्थितियाँ। उत्तरदाताओं ने नहीं किया है किसी भी परिस्थिति के अस्तित्व को बढ़ाया जिसकी आवश्यकता थी किसी भी स्वयंसेवकों की छुट्टी, न ही ऐसा आग्रह किया गया है ऐसी कोई शर्त मौजूद है जिसकी आवश्यकता होगी अपीलकर्ताओं को विशेष रूप से इसके अलावा आरोपमुक्त किया जाना चाहिए अनुशासनहीनता का आरोप. इसलिए, हमारे विचार में, की सेवाएँ अपीलकर्ताओं को कथित कदाचार के कृत्यों के लिए आरोपमुक्त किया जाता है। यह उनकी योग्यता पर कलंक लगाता है और उनके भविष्य को प्रभावित करता है आजीविका।

(31) हमारे विचार में, मुक्ति के मामलों में भी,जबकि संबंधित प्राधिकारी मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता एक कर्मचारी को छुट्टी देना. हालाँकि, मौजूदा मामले में, अपीलकर्ताओं को सेवा से बर्खास्त किया जा रहा है अनुशासनहीनता इसलिए, जैसा कि नियम 27 के परंतुक में दिया गया है नियमों के अनुसार, अपीलकर्ताओं को उचित जानकारी दी जानी चाहिए थी प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का अवसर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. माना कि ऐसा कोई अवसर नहीं था उन्हें दिया गया. इसलिए, हमारा मानना है कि कार्रवाई उत्तरदाताओं का यह कथन उनके अपने वैधानिक नियमों के विपरीत है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

(32) यहां तक कि इस प्रश्न में गए बिना भी कि क्या अपीलकर्ता अनुच्छेद 311 के तहत सुरक्षा के पात्र हैं संविधान, हमारे विचार में, उत्तरदाताओं के पास प्रतीत होता है की सेवाएं समाप्त कर मनमाने ढंग से कार्य किया अपीलकर्ता, जो होम गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं पिछले 15-17 साल. वे सभी अधिक उम्र के हैं। वे पा सकते हैं वैकल्पिक

रोज़गार ढूँढना कठिन है। इसलिए, में इस मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ और हित में न्याय, हम इस आदेश को रद्द करना उचित समझते हैं उत्तरदाताओं द्वारा दिनांक 02.12.2004 को समाप्ति पारित की गई प्रतिवादियों को अपीलकर्ताओं को गृह के रूप में बहाल करने का निर्देश दें बिना बकाया वेतन के गार्ड.

(33) केस से अलग होने से पहले हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उठाया गया छोटा सा मुद्दा उत्तरदाताओं यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता बिना के नियम 27(3) के तहत प्रदान किए गए अपील उपचार को समाप्त करना 1963 के नियमों के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता था संविधान का अनुच्छेद 226, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुरोध करता है उच्च न्यायालय प्रतिवादियों द्वारा दिनांकित पारित आदेश को रद्द करेगा 02.12.2004. हमें उनके समर्पण में कोई योग्यता नहीं दिखती, इस कारण से कि यह मुद्दा न तो उठाया गया और न ही बहस की गई उच्च न्यायालय के समक्ष और इसलिए, हम इसकी अनुमति नहीं देंगे हमारे सामने पहली बार उठाया जाने वाला मुद्दा. ये भी तर्क दिया कि निर्देशों के सार-संग्रह के पैरा 14.4 पर होम गाड़र्स कमांडेंट जनरल या को अधिकृत करता है कमांडेंट को किसी भी समय, यदि कोई हो, होम गार्ड को छुट्टी देनी होगी उनकी राय है, होम गार्ड की सेवाएं अब नहीं हैं आवश्यक। ये निर्देश नियम 18 की पुनरावृत्ति हैं नियम। हम पहले ही इन नियमों से निपट चुके हैं। इसलिए, हमारे तर्क को एक बार फिर से दोहराना संभव नहीं होगा ज़रूरी।"

(15) 1963 के नियमों का नियम 27 इस प्रकार है:-

“27. बर्खास्तगी - (1) कोई भी सदस्य, कदाचार के लिए या बिना पर्याप्त कारण के कर्तव्य से अनुपस्थित रहने पर बर्खास्त किया जायेगा सेवा से: परन्तु यह कि जब तक बर्खास्तगी का कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा बर्खास्तगी के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाता है और सदस्य संबंधित को उचित अवसर दिया गया है की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताना उसके खिलाफ।

(2) बर्खास्तगी का आदेश पारित करने में सक्षम प्राधिकारी राजपत्रित अधिकारी का मामला सरकार का होगा और अराजपत्रित अधिकारी और अन्य के मामले में सदस्य, कमांडेंट-जनरल या ग्राम रक्षा दल प्रमुख, जैसी भी स्थिति हो।

(3) द्वारा पारित बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ अपील कमांडेंट जनरल या ग्राम रक्षा दल प्रमुख से झूठ बोला जाएगा सरकार।

(4) उप नियम (2) के तहत पारित शासन का आदेश या उप-नियम (3) अंतिम होगा और इसमें शामिल नहीं किया जाएगा किसी भी कार्यवाही में प्रश्न पूछें।

(16) उपरोक्त नियम के अनुसार यदि बर्खास्तगी का आदेश होना है पारित, सबसे पहले कारणों को दर्ज करना होगा और संबंधित सदस्य को के विरुद्ध कारण बताने का उचित

अवसर दिया जाना चाहिए उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित है. माना कि ऐसा कोई शो नहीं है याचिकाकर्ता को कारण सूचना या व्यक्तिगत सुनवाई दी गई है। यह है यह भी स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए थी उनके खिलाफ कदाचार यानी पंजाब के तहत एफआईआर दर्ज करना एक्साइज एक्ट और ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर जो इसके अंतर्गत आएगा 1963 नियमावली के नियम 27 के प्रावधान।

(17) अब प्रतिवादियों द्वारा जो दलील दी जा रही है वह है किसी गृह के निर्वहन हेतु सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों के बारे में 1963 नियमावली के नियम 18 के तहत गार्ड। मुक्ति की उक्त शक्ति नियम 18 के तहत यद्यपि उक्त नियमों के तहत प्रावधान किया गया है लेकिन वह मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह मुद्दा जो खोजा जा रहा है उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी उठाया गया था देविंदर सिंह के मामले में कोर्ट (सुप्रा), जिसका जवाब दिया जा चुका है तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नकारात्मक और मामले की परिस्थितियाँ, जहाँ न्यायालय एक निष्कर्ष पर पहुँचा था जिसके कारण डिस्चार्ज सरलीकरण का आदेश पारित किया गया है वर्तमान मामले में कर्तव्य से अनुपस्थिति, जो इससे स्पष्ट है अनुलग्नक पी-1 (कोली) पर टिप्पणियाँ। याचिकाकर्ता का मामला कवर हो गया है सभी पहलुओं पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुपात से दविंदर सिंह का मामला (सुप्रा)। इसलिए, आक्षेपित आदेश है अस्थिर.

(18) एक और पहलू जिस पर वकील ने प्रकाश डाला है उत्तरदाताओं का कहना है कि याचिकाकर्ता की ओर से संपर्क करने में देरी हो रही है बहाली के लिए सक्षम प्राधिकारी, यह कहना पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता ने मुकदमे के समापन का इंतजार किया और यह फैसले के बाद है अदालत ने, जिसने उसे निर्दोष घोषित किया, उसने अदालत से संपर्क किया था आदेश वापस लेने हेतु निर्णय की प्रति के साथ सक्षम प्राधिकारी उनकी सेवा से बर्खास्तगी के संबंध में। इस प्रक्रिया में, कुछ हुआ है देरी, इसमें कोई संदेह नहीं, अपनी ओर से, लेकिन एक आदर्श और कर्तव्यनिष्ठ नियोक्ता के रूप में, किसी के ऐसे अनुरोध पर विचार करना प्राधिकारी का परम कर्तव्य है कर्मचारी विशेष रूप से टिप्पणियों के आलोक में, जो किया गया है निचली अदालत ने उसे लगाए गए आरोपों से बरी करते हुए यह आदेश दिया। नहीं केवल इतना ही, न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर बहुत स्पष्ट रूप से कहा है पर गलत वसूली थोपे जाने की संभावना देखी गई याचिकाकर्ता को खारिज नहीं किया जा सकता. न्यायालय की ऐसी टिप्पणियों की आवश्यकता है सक्षम प्राधिकारी की ओर से इस पर गंभीरता से विचार किया जाना है कम से कम के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए एक उचित निष्कर्ष पर पहुँचें याचिकाकर्ता, जिसका, माना जाता है, जवाब नहीं दिया गया है और जो जवाब दाखिल किया गया था उसमें जो आपत्तियां ली गई हैं यह पांच महीने से अधिक की अवधि के बाद प्रस्तुत किया गया है उसका बरी होना. उत्तरदाताओं की ओर से यह दृष्टिकोण वर्तमान मामले के अजीबोगरीब तथ्य और परिस्थितियाँ सामने आईं अनुचित. इसलिए, उत्तरदाताओं की आपत्ति के संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से सबसे पहले संपर्क करने में देरी हो रही है उत्तरदाताओं और उसके बाद, इस न्यायालय में इसे स्वीकार नहीं किया जाता है इस न्यायालय के विचार से, याचिकाकर्ता ने सामान्य के रूप में कार्य किया है दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में उचित व्यक्ति के पास होगा।

(19) अब उन निर्णयों पर आते हैं जिन पर निर्भरता रही है उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा रखा गया। सबसे पहले है गौरी में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा सुनाया गया निर्णय शंकर का मामला (सुप्रा), यह एक ऐसा मामला है जहां केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र पर विचार कर रहा था, जो ऐसा प्रदान किया गया है प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 14 अध्याय III के तहत। इसी संदर्भ में उक्त न्यायालय की यह टिप्पणी आयी थी। जिसमें यह माना गया है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने ऐसा नहीं किया याचिकाकर्ता द्वारा पसंद किए गए

आवेदन पर विचार करने की शक्ति है, जो होम गार्ड्स स्वयंसेवी संगठन का हिस्सा थे केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर इसका दायरा नहीं बढ़ाया था धारा 14 के तहत न्यायाधिकरण ऐसी याचिका पर विचार करेगा होम गार्ड स्वयंसेवक के कर्मचारी। उक्त निर्णय, इसलिए, किसी भी तरह से इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत प्रदान की गई ऐसी कोई मोटी बात नहीं है, जहां का अधिकार क्षेत्र हो ऐसा न्यायाधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 14 के अनुसार प्रतिबंधित है।

(20) उत्तरदाताओं के वकील ने इस पर भरोसा जताया है जतिंदर सिंह के मामले में इस न्यायालय का निर्णय (सुप्रा) जहां एक मामले में संविदा कर्मचारी के मामले में, इस न्यायालय ने माना है कि ऐसा कर्मचारी में शामिल होने के बाद पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं था आपराधिक मामला, बाद में सेवा में बहाली के लिए बरी होने पर समाप्ति के बाद, यह कहना पर्याप्त होगा कि ऐसी टिप्पणियाँ आई थीं उक्त मामले के विशिष्ट तथ्य और परिस्थितियाँ जब वह संलग्न थे परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में एक परिचारक के रूप में पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जालंधर, जहां के खिलाफ आरोप है वह छात्रों की अटेम्प्टेड शीटों को प्रतिस्थापित करने के बारे में थे कार्यालय की मोहरें लगाने के बाद गढ़ी हुई चादरें, जो थीं भारी रकम के लिए विश्वविद्यालय परिसर से चोरी की गई विद्यार्थियों से प्राप्त किया जाना है। इसलिए, उक्त निर्णय होगा किसी भी तरह से मौजूदा मामले पर लागू नहीं होगा क्योंकि यह संबंधित नहीं है एक नियुक्ति जो अधिनियम और वैधानिक नियमों के तहत की जाती है वर्तमान मामले की तरह ही इसके तहत तैयार किया गया है।

(21) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि के निर्णय से याचिकाकर्ता का मामला उसके पक्ष में आ जाता है दविंदर सिंह के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रा), जो राकेश कुमार के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है (सुप्रा), वर्तमान रिट याचिका अनुमति दिये जाने योग्य है। इसलिए आक्षेपित आदेश दिनांक 21.09.2016 (अनुलग्नक पी-2) को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

(22) याचिकाकर्ता को तत्काल सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया जाता है सेवा में निरंतरता के साथ. याचिकाकर्ता सबका हकदार होगा पहले के वास्तविक वित्तीय लाभों को छोड़कर परिणामी लाभ उसके बाद बहाली के लिए उसके अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की तिथि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें उन्हें बरी कर दिया गया.

तेजिंदरबीर सिंह

अस्वीकरण -

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिये है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समज सके और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका

उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिये निर्णय का अंगरेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन कार्यावयन

के उददेश्य के लिये उपयुक्त रहेगा ।

सुरेश पाल सन्धु